

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) No authorisations for supply of cement were issued on Jaipur Udyog Ltd. Jaipur during January 1971, by Regional Cement Officer, Bombay.

(b) Does not arise.

(c) to (e). M/s. Patel Tiles & Marbles (P) Ltd., Bombay were issued authorisations for a quantity of 72 metric tonnes in January, 1975 and another authorisation for 48 metric tonnes in March, 1975 on M/s. Jaipur Udyog Ltd., Swaimadhapur. Due to certain difficulties faced by the management including less production, closure of the cement factory etc., M/s. Jaipur Udyog Ltd. could not supply cement to this party. On receipt of a complaint in this regard from the party, the authorisations issued on M/s. Jaipur Udyog Ltd. were cancelled and fresh authorisations for 120 metric tonnes were issued on M/s. A.C.C. Wadi Wadi Cement factory.

वार्षिक विकास दर

2097. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 में वार्षिक विकास की दर क्या थी ; और

(ख) चालू और आगामी वर्ष के दौरान यह विकास की दर कितनी होने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) 1976-77 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की विकास दर 1.5 से 2.0 प्रतिशत के बीच होने की संभावना है ।

(ख) अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं है ।

दामोदर घाटी परियोजना

2098. श्री रामामन्द तिवारी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी परियोजना के अन्तर्गत बिहार के पानी का उपयोग सिंचाई एवं बिजली के उत्पादन के लिए होता है परन्तु इसका सर्वाधिक लाभ पश्चिम बंगाल को ही मिलता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस विषयता को दूर करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :

(क) से (ग) दामोदर घाटी परियोजना के अन्तर्गत दामोदर नदी के जल का उपयोग सिंचाई, विद्युत-उत्पादन तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है तथा जिस सीमा तक व्यवहार्य है उस सीमा तक बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों को इससे लाभ मिलता है । दामोदर नदी के जल का उपयोग करने के लिए बिहार सरकार की ओर से दो सिंचाई स्कीमों का प्रस्ताव है, नामशः तिलैया व्यपवर्तन स्कीम तथा कोनार व्यपवर्तन स्कीम । बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकारों एवं दामोदर घाटी निगम द्वारा इन प्रस्तावों की जांच की जानी है तथा इन पर विचार किया जाना है ।

तटीय राजपथों का निर्माण और उनकी लम्बाई

2099. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या नौबहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में केन्द्रीय सहायता के साथ निर्माण किए गए तटीय राजपथों की कुल लम्बाई क्या है ;

(ख) गुजरात राज्य में निर्माण किए गए तटीय राजपथों की लम्बाई क्या है ;

(ग) गुजरात राज्य को अब तक कुल कितना अनुदान दिया गया ; और

(घ) गुजरात को 1977-78 के दौरान कितना अनुदान दिया जाना है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (घ). गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा के राज्यों में केन्द्रीय सहायता से 1621 कि०मी० तटीय राज्य सड़कों की व्यवस्था की गयी है ।

जहां तक, गुजरात में तटीय राज्य राजमार्ग का सम्बन्ध है, वास्तव में इसकी लम्बाई 1824 कि०मी० है, जिसमें काफी बड़ी लम्बाई की सड़क पहले से ही मौजूद हैं और कुछ लुप्त योजक-मार्गों तथा उन पर पुलों के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है । इसके लिए अब तक स्वीकृत सहायता 443.50 ला आती है ।

अप्रैल जुलाई, 1977 के दौरान व्यय के लिए, लेखा में स्वीकृत धनराशि में से 28.00 लाख रु० की राशि इस प्रयोजन के लिए दी गयी है । वर्ष की शेष अवधि के लिए संसद द्वारा अनुदान की मांगें पारित होने के बाद धन का आवंटन किया जाएगा ।

उपर्युक्त तटीय राज्य सड़कों के अतिरिक्त, तटीय क्षेत्रों में लगभग 5400 कि०मी० लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्ग भी हैं, जिनका विकास और अनुरक्षण व्यय पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है । 5400 कि०मी० की इस लम्बाई में बम्बई के पास पानवेल से कोचीन के निकट एरापल्ली तक पश्चिमी तट सड़क भी शामिल है जो मार्च, 1972 तक केन्द्रीय सहायता प्राप्त राज्य सड़क थी और उसके बाद उसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया ।

Wind Electric Generator

2100. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the National Aeronautical Laboratory (NAL), Bangalore, has designed and developed a wind electric generator; and

(b) if so, facts regarding its functioning?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) The device is capable of producing better than 20 to 30 volt ampere hours of energy on a windy day and is economically viable as an alternate to drycell usage. Its applications are for use in communication repeater stations, navigation buoys in seaways, aviation lighting equipment on isolated physical features. As and when the wind energy is available the Wind Electric Generator charges a long life battery from which the energy can be drawn. The present status of the system is that tests on prototype are in final stages.

Plants for Extraction of Oil from Coal

2101. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether a decision has been taken to establish plants at four places to extract oil from coal;

(b) if so, main features thereof;

(c) whether Government will need any foreign know-how for extracting oil from coal; if so, facts thereof; and

(d) total expenditure expected on this project?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) No Sir.